

नाम बड़े, रसोई बेहाल: कानपुर के होटल-रेस्तरां में 'शुद्ध' का सच उजागर, 10 आउटलेट बंद; कई पर लाइसेंस कार्रवाई

‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: कहीं किचन में कीड़े, कहीं एक्सपायर्ड सॉस, कहीं फर्श पर रखा मिला खाना; पांच प्रतिष्ठानों का कारोबार बंद कराया गया

कानपुर। शहर के चमकते मॉल और नामी होटल-रेस्तरां के पीछे खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के दावों की एक अलग तस्वीर सामने आई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) के ‘शुद्ध ही शुभ है’ अभियान के तहत हुई जांच में किचन की गंदगी, खाद्य सामग्री के गलत भंडारण, कीड़े-मकौड़ों की मौजूदगी और वेज-नॉनवेज के लिए एक ही बर्तनों के इस्तेमाल जैसी गंभीर कमियां सामने आईं। अभियान के एक चरण में कानपुर में 38 टीमों ने 52 फूड यूनिट और रेस्टोरेंट की जांच की, जिसके बाद रेव मोती मॉल के फूड कोर्ट के सभी 10 आउटलेटों को सुधार होने तक बंद करा दिया गया। जेड स्क्वायर मॉल स्थित ला पीनोज पिज्जा का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति भी की गई।

कहीं कीड़े, कहीं एक्सपायर्ड सामान जांच के दौरान रेव मोती मॉल के फूड कोर्ट में स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब मिली। रिपोर्ट के मुताबिक किचन की दीवारों पर गंदगी जमी थी और खाद्य सामग्री फर्श पर रखी मिली, जिस पर मक्खियां मंडरा रही थीं। ला पीनोज पिज्जा की जांच में खाद्य पदार्थों में कीड़े, एक्सपायर्ड सॉस और चटनी तथा खराब गुणवत्ता का पनीर मिलने की बात सामने आई। टीम को वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों के लिए एक ही बर्तनों के इस्तेमाल

की स्थिति भी मिली। इन कमियों के आधार पर विभाग ने लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की।

जेड स्क्वायर मॉल के नाई हाऊ (Nai Hao) प्रतिष्ठान में नाली चोक मिली और किचन में गंदगी के साथ वेज-नॉनवेज के लिए साझा बर्तनों के इस्तेमाल की रिपोर्ट सामने आई। यहां कारोबार सुधार होने तक बंद कराया गया। वहीं बिरयानी क्वीन में आटे में कीड़े मिलने, निर्माण स्थल पर अत्यधिक गंदगी और खाद्य तेल के बार-बार इस्तेमाल की बात जांच रिपोर्टों में सामने आई। ग्लोबल बेकर्स एंड कैफे, हरबंस मोहाल में किचन की खराब स्वच्छता, वेज-नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक साथ तैयार करने और जल निकासी की खराब व्यवस्था पाए जाने की सूचना है।

टुंडे कबाबी पर भी कड़ी कार्रवाई अभियान के इसी चरण में टुंडे कबाबी, कानपुर भी जांच के दायरे में आया। विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट के अनुसार



यहां खाद्य प्रोसेसिंग क्षेत्र में दुर्गंध, कच्चे मांस के रखरखाव में खामियां और वेज-नॉनवेज खाद्य पदार्थों के पृथक्करण का अभाव मिला। इसके आधार पर प्रतिष्ठान के लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई/संस्तुत की गई। राज्य सरकार के 22 सितंबर के आधिकारिक संचार तथा रिपोर्टेड कवरेज में टुंडे कबाबी का नाम उन प्रतिष्ठानों में शामिल है, जिनके खिलाफ लाइसेंस संबंधी कार्रवाई की गई।

दूसरे चरण में पांच प्रतिष्ठानों का कारोबार बंद

अभियान के 25 सितंबर के अगले चरण में राज्य सरकार ने छह जिलों में 291 खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की जानकारी दी। इनमें कानपुर नगर के 52 प्रतिष्ठान शामिल थे। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गंभीर कमियां पाए जाने पर कानपुर के पांच प्रतिष्ठानों का कारोबार बंद करा दिया गया। इनमें काके की हट्टी रेस्टोरेंट, मॉल रोड; एम/एस आनंद सैफ्रॉन होटल, हर्ष नगर; द डाइनिंग हाउस, आवास-विकास कल्याणपुर; रेवंत हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड-लिटिल शेफ, सिविल लाइंस; और एम/एस अल समीम फूड कोर्ट, जाजमऊ शामिल हैं। विभाग ने इन सभी स्थानों पर स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब पाए जाने की बात कही। इसी चरण में प्रदेशभर में 24 प्रतिष्ठानों के



खिलाफ लाइसेंस निलंबन और अन्य विधिक कार्रवाई की संस्तुति तथा 174 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस दिए गए। जांच में स्वच्छता, खाद्य भंडारण, कच्चे माल की गुणवत्ता, किचन व प्रोसेसिंग एरिया, जल निकासी, कीट नियंत्रण और वेज-नॉनवेज खाद्य पदार्थों को अलग रखने जैसी व्यवस्थाओं को जांचा गया। सरकारी विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि अभियान आगे जारी रहेगा।

कानपुर की कार्रवाई ने उठाए बड़े सवाल खाद्य विभाग की इस मुहिम ने सिर्फ मिलावट

की समस्या नहीं, बल्कि रेस्तरां की रोजमर्रा की किचन हाइजीन और फूड-हैंडलिंग व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। उपभोक्ता जिस प्रतिष्ठान को बाहर से साफ-सुथरा और ब्रांडेड मानकर भोजन के लिए चुनता है, उसके पीछे की रसोई में स्वच्छता का स्तर खराब हो सकता है। हालिया निरीक्षणों में सामने आई कमियां इसी ओर इशारा करती हैं। साथ ही, विभाग की कार्रवाई यह भी बताती है कि जांच अब केवल खाद्य पदार्थ के नमूने लेने तक सीमित नहीं रही, बल्कि कंटेमिनेशन जैसे पहलुओं तक पहुंच रही है।

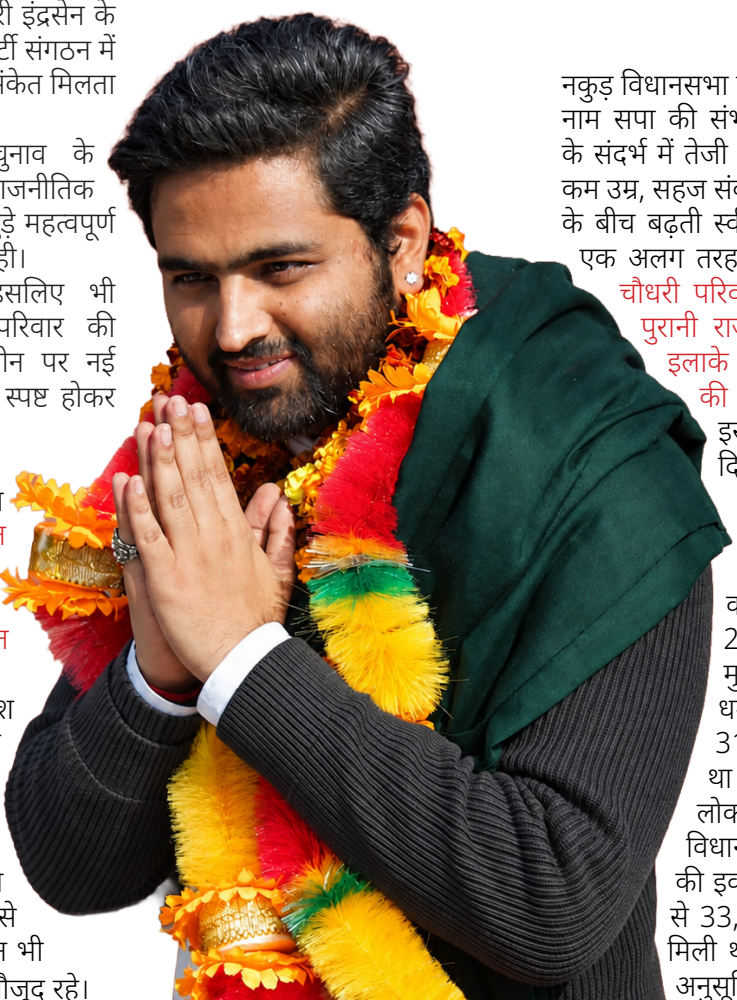
राजनीति की नई पीढ़ी में सहारनपुर का उभरता युवा चेहरा सियासी विरासत और लगातार सक्रियता ने परीक्षित चौधरी को दिलाई मजबूत पहचान; नकुड़ विधानसभा से साबित होंगे सपा के युवा तुर्क

सहारनपुर की सियासत में नई पीढ़ी के कई युवा चेहरे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच समाजवादी विचारधारा के एक युवा ने अपना परचम बुलंद करा है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों में मौजूदगी से परीक्षित चौधरी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मिलनसार व्यक्तित्व, शानदार वक्तृत्व, मुद्दों पर मजबूत पकड़ और सियासी विरासत ने परीक्षित चौधरी को युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय और स्वीकार्य चेहरा बनाया है। स्व: चौधरी यशपाल सिंह की सियासी विरासत और पिता चौधरी इंद्रसेन की सक्रिय राजनीति के बीच परीक्षित अब उस अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर सहारनपुर सपा की नजरें टिकी हैं।

कम उम्र में काम से बढ़ाया क्रद परीक्षित की राजनीतिक यात्रा की खास बात यह है कि उन्होंने कम उम्र में ही संगठन और जमीनी राजनीति दोनों में सक्रियता दिखाई। 2021 के किसान आंदोलन के दौरान वह युवा सपा नेता के रूप में किसानों के जत्थे का नेतृत्व करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। उसी दौर में पार्टी के स्थानीय धरना-प्रदर्शनों और संगठनात्मक गतिविधियों में भी

उनकी मौजूदगी दर्ज हुई। इसके अलावा, 2021 में सपा नेतृत्व के साथ हुई बैठकों में भी वह अपने पिता चौधरी इंद्रसेन के साथ नजर आए, जिससे पार्टी संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका का संकेत मिलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चौधरी परिवार की राजनीतिक गतिविधियों और सपा से जुड़े महत्वपूर्ण बैठकों में उनकी मौजूदगी रही। यह दौर उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि परिवार की पारंपरिक राजनीतिक जमीन पर नई पीढ़ी की मौजूदगी अधिक स्पष्ट होकर सामने आई।

2026 में उनकी सक्रियता का दायरा और बढ़ा। अगस्त में देवबंद में आयोजित सपा की पीडीए पंचायत को परीक्षित चौधरी ने संबोधित किया। 2 सितंबर को अखिलेश यादव ने चौधरी परिवार के आवास पर पांच घंटे से अधिक समय बिताया, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की और मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान भी परीक्षित प्रमुख भूमिका में मौजूद रहे।



नकुड़ में सपा को उम्मीद, परीक्षित हो सकते हैं ट्रम्प कार्ड

नकुड़ विधानसभा में परीक्षित चौधरी का नाम सपा की संभावित युवा राजनीति के संदर्भ में तेजी से चर्चा में है। उनकी कम उम्र, सहज संवाद शैली और युवाओं के बीच बढ़ती स्वीकार्यता उन्हें क्षेत्र में एक अलग तरह की अपील देती है। चौधरी परिवार की सहारनपुर में पुरानी राजनीतिक पकड़ और इलाके में गुर्जर मतदाताओं की महत्वपूर्ण मौजूदगी इस समीकरण को और दिलचस्प बनाती है।

नकुड़ का चुनावी इतिहास भी इस चर्चा को आधार देता है। 2022 में भाजपा के मुकेश चौधरी ने सपा के धर्म सिंह सैनी को सिर्फ 315 वोटों से हराया था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से सपा की इकरा हसन को भाजपा से 33,791 वोटों की बढ़त मिली थी। नकुड़ में मुस्लिम, अनुसूचित जाति, गुर्जर और

सैनी मतदाताओं की बड़ी मौजूदगी इसे बहुस्तरीय सामाजिक समीकरण वाली सीट बनाती है। क्षेत्र के जटिल सामाजिक समीकरणों के बीच परीक्षित जैसे युवा और स्थानीय राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले चेहरे की मौजूदगी सपा के लिए संगठन को मजबूत करने का एक संभावित रास्ता बन सकती है।

2026 के Gen Z प्रदर्शनों के बाद अलग-अलग दलों में युवाओं को संगठन और नेतृत्व में अधिक जगह देने तथा युवा चेहरों को आगे लाने पर जोर बढ़ा है। इसी बदलते माहौल में परीक्षित चौधरी जैसे युवा नेताओं की भूमिका और संभावनाएं भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

नकुड़ से उनका उभार सपा की उस कोशिश का हिस्सा भी माना जा सकता है, जिसमें नई पीढ़ी के नेताओं को सामने लाने की जरूरत बढ़ी है।

ऐसे में उनकी उम्मीदवारी चौधरी परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ-साथ सहारनपुर सपा में नई पीढ़ी के नेतृत्व को स्थापित करने का संकेत भी होगी।

बारिश से बेहाल उत्तर प्रदेश : मानसून की विदाई ने छोड़े तबाही के निशान

48 घंटे में 15 मौतें, 117 मकान क्षतिग्रस्त; 63 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश, फसल से लेकर सड़क और बिजली व्यवस्था तक प्रभावित

लखनऊ।

सितंबर के आखिरी दिनों में हुई लगातार और असामान्य बारिश ने उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई को मुश्किल दौर में बदल दिया। 24 से 26 सितंबर के बीच प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज बारिश, आंधी और गरज-चमक ने जनजीवन प्रभावित किया। शहरों में सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ तो गांवों में कच्चे मकानों, बिजली के ढांचे और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आशंका फिर उभरी। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक, इस बारिश और खराब मौसम से जुड़े हादसों में 48 घंटे के दौरान 15 लोगों की मौत, पांच लोग घायल और चार पशुओं की मौत हुई। प्रदेश में 117 मकानों को नुकसान पहुंचा। इसी अवधि में 63 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई।

लखनऊ से बुंदेलखंड तक आसमान ने खोला मोर्चा

बारिश की तीव्रता का अंदाजा अलग-अलग जिलों में दर्ज आंकड़ों से लगाया जा सकता है। बांदा में एक दिन में 146 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बहराइच में 103.6 मिमी बारिश हुई। बाराबंकी में 62.4 मिमी, हमीरपुर में 54 मिमी, हरदोई में 37 मिमी, लखीमपुर खीरी में 35 मिमी, शाहजहांपुर में 33.8 मिमी और कानपुर नगर में 32.2 मिमी बारिश दर्ज हुई। इससे पहले से नम जमीन और जलनिकासी की सीमित क्षमता वाले इलाकों में स्थिति तेजी से बिगड़ी।

राजधानी लखनऊ भी इस बारिश की तीव्रता से अछूती नहीं रही। शुक्रवार सुबह से शनिवार तड़के तक करीब 21 घंटे में 125.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार पानी गिरने के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ और सड़क यातायात प्रभावित रहा। कुछ इलाकों में निचली सड़कों और संपर्क मार्गों पर लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा।

48 घंटे में 15 मौतें, दर्जनों परिवार प्रभावित

बारिश केवल असुविधा तक सीमित नहीं रही। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, विभिन्न जिलों में दीवार, मकान और अन्य ढांचों के गिरने तथा खराब मौसम से जुड़े हादसों में 15 लोगों की मौत हुई। लखीमपुर खीरी में चार, अयोध्या में दो तथा अमेठी, बहराइच, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई और कानपुर नगर में एक-एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई। पांच लोग घायल भी हुए। मकानों के नुकसान का सबसे बड़ा असर बुंदेलखंड और मध्य यूपी के कुछ हिस्सों में देखा गया। बांदा में 32, जालौन में 21 और हरदोई में 14 मकानों को नुकसान पहुंचा। औरैया तथा पीलीभीत में सात-सात, जबकि बहराइच और सुल्तानपुर में पांच-पांच मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दर्ज की गई। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों और कमजोर दीवारों पर लगातार बारिश तथा तेज हवा का सबसे अधिक असर पड़ा।

कानपुर में भी बारिश ने बदली शहर की रफ्तार

कानपुर में लगातार बारिश से शहर के



कई हिस्सों में जलभराव और यातायात की समस्या सामने आई। 25 सितंबर तक शहर में सितंबर महीने में 232.8 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी थी, जबकि सितंबर का सामान्य औसत करीब 169 मिमी है। लगातार बारिश के चलते तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई। सड़कों पर जमा पानी, गड्ढों और खराब हिस्सों ने कई इलाकों में आवाजाही को मुश्किल बनाया।

बारिश का असर सामान्य प्रशासनिक कामकाज और शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा। कानपुर नगर में 26 सितंबर को प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। खराब मौसम को देखते हुए यह फैसला स्थानीय सुरक्षा परिस्थितियों के आधार पर लिया गया।

खेतों पर पड़ी बारिश की दूसरी मार

सितंबर के अंतिम सप्ताह की बारिश ने किसानों के लिए अलग तरह की मुश्किल पैदा की। कई इलाकों में धान और अन्य खड़ी फसलों पर तेज हवा के साथ हुई बारिश का असर पड़ा। खेतों में पानी भरने और फसल के झुकने से नुकसान की आशंका बढ़ी। अयोध्या समेत कई जिलों से धान और गन्ने जैसी खड़ी फसलों पर तेज हवा और बारिश के असर की रिपोर्टें सामने आईं। सरकार ने जिलों को अत्यधिक बारिश और आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवारों और किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि मानसून के अंतिम चरण में फसलें खेतों में खड़ी थीं और कई जगह कटाई की तैयारी चल रही थी। ऐसे समय पर कुछ घंटों में होने वाली बहुत तेज बारिश सामान्य मानसूनी बारिश की तुलना में अधिक नुकसान कर सकती है।

नदियों और निचले इलाकों में बढ़ी चिंता

बारिश के साथ नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी ने कई इलाकों में दूसरी चिंता खड़ी की। चित्रकूट में लगातार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया और रामघाट का निचला हिस्सा प्रभावित हुआ। वहीं नेपाल में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंडक नदी से जुड़े इलाकों पर भी निगरानी बढ़ाई गई।

राज्य के कई जिलों को अचानक बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील माना गया। इनमें आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकरनगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, फतेहपुर, कानपुर नगर, बांदा, कौशांबी और चित्रकूट शामिल थे।

बारिश की वजह बना मौसम तंत्र

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पूरे दौर के पीछे मध्य भारत के ऊपर बना निम्न दबाव तंत्र महत्वपूर्ण कारण रहा। उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर बना डिप्रेशन उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आया। इसी मौसम प्रणाली के कारण प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में व्यापक बारिश की स्थिति बनी। कानपुर में मौसम विशेषज्ञों ने भी एक से अधिक मौसम प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव को बारिश के इस दौर की वजह बताया था। इससे मानसून की गतिविधि सितंबर के अंतिम सप्ताह में अचानक तेज हुई और कई जिलों में कम समय में

काफी बारिश रिकॉर्ड हुई।

एक दिन में सामान्य से 19 गुना बारिश

बारिश की असामान्यता केवल स्थानीय स्तर के आंकड़ों में नहीं दिखी। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, प्रदेश ने 24 घंटे की अवधि में अपने सामान्य आंकड़े से करीब 19 गुना अधिक बारिश दर्ज की। फर्रुखाबाद में सामान्य से लगभग 200 गुना और कानपुर नगर में करीब 160 गुना बारिश दर्ज होने की जानकारी दी गई। कुल 63 जिलों में बारिश सामान्य से ऊपर रही। फिर भी पूरे मानसून की तस्वीर को केवल इन कुछ दिनों की बारिश के आधार पर नहीं देखा जा सकता। 25 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश दीर्घकालिक औसत से लगभग पांच प्रतिशत कम थी, जिसे मौसम विभाग सामान्य श्रेणी में रखता है। यानी पूरे सीजन का आंकड़ा अपेक्षाकृत सामान्य रहा, लेकिन सितंबर के अंतिम दिनों में हुई अत्यधिक बारिश ने कई जिलों में स्थानीय स्तर पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया।

प्रशासन के सामने बारिश के बाद की चुनौती

बारिश के दौरान प्रशासन ने बाढ़, जलभराव, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं से निपटने के लिए जिलाधिकारियों तथा राहत-बचाव एजेंसियों को सक्रिय रखा। संवेदनशील जिलों की निगरानी बढ़ाई गई और प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को बारिश और बिजली गिरने से हुए नुकसान का आकलन कर पीड़ित परिवारों को निर्धारित समय में सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया। लेकिन बारिश थमने के बाद भी कई जिलों में मुश्किलें तुरंत खत्म नहीं हुईं। जलभराव वाले इलाकों में पानी की

निकासी, क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे, बिजली आपूर्ति की बहाली, ग्रामीण संपर्क मार्गों की मरम्मत और फसलों के नुकसान का आकलन प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारियां बनकर उभरे। नदियों में बढ़े जलस्तर ने भी यह सुनिश्चित किया कि बारिश बंद होने के बावजूद निचले इलाकों में सतर्कता बरकरार रखनी पड़ी।

मानसून की विदाई, लेकिन पीछे छोड़ गया बड़ा सवाल

उत्तर प्रदेश में इस वर्ष मानसून की शुरुआत सामान्य समय से कुछ हद तक देर से हुई थी, और शुरुआती महीनों में हुई बारिश का वितरण पूरे प्रदेश में समान रूप से नहीं था। सितंबर के अंतिम सप्ताह में अचानक हुई भारी बारिश ने मानसून के सीजन के अंत की पूरी तस्वीर एकदम बदल कर रख दी। कुछ ही घंटों में हुई इस अत्यधिक बारिश ने जहां शहरों की जलनिकासी व्यवस्था की कमजोरियों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया, वहीं ग्रामीण इलाकों में कमजोर और अधूरी संरचनाओं वाले मकानों तथा खड़ी फसलों की संवेदनशीलता भी सामने आई, जिससे वहां के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बारिश का यह दौर अब मौसम के कैलेंडर में एक बीते हुए घटनाक्रम के रूप में दर्ज हो चुका है, लेकिन इसके प्रभाव और निशान कई जिलों में कुछ समय तक बने रहेंगे। इस बार मानसून की विदाई उत्तर प्रदेश के लिए शांतिपूर्ण नहीं रही, क्योंकि 15 लोगों की मौत, 117 क्षतिग्रस्त मकान, जलमग्न खेत, प्रभावित सड़कें और बढ़े हुए नदी जलस्तर इस बात का स्पष्ट सबूत हैं। अब सवाल केवल यह नहीं कि इस बार कितना पानी बरसा, बल्कि यह भी है कि इतनी कम अवधि में गिरे भारी पानी से निपटने के लिए शहरों और गांवों की तैयारियां और व्यवस्थाएं कितनी प्रभावी और सक्षम थीं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 60 हजार पन्नों की चार्जशीट SIT की जांच में 105 बार नकदी निकालने या छिपाने के आरोप, 173 गवाहों के बयान और आरोपियों के बैंक खातों से लेकर संपत्तियों तक की पड़ताल

अयोध्या के प्रतिष्ठित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के संदर्भ में विशेष जांच दल (SIT) ने आठ आरोपियों के विरुद्ध 60 हजार से अधिक पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में मंदिर में आने वाली नकदी के संग्रह, उसकी गिनती, बैंक तक सुरक्षित पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया, मंदिर में चढ़ावे के रूप में प्राप्त कीमती वस्तुओं और आरोपियों के वित्तीय लेन-देन की गहन और व्यापक जांच शामिल है। यह जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित SIT द्वारा की गई है, जो मामले की गंभीरता को दर्शाती है।

जांच के दौरान SIT ने विशेष तौर पर मंदिर परिसर में नकदी की गिनती और उसे अलग-अलग करने की प्रक्रिया पर गहरा ध्यान केंद्रित किया। अधिकारियों के मुताबिक, CCTV फुटेज, गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से जांच में 105 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें नकदी को कथित तौर पर बिना अनुमति निकालने या छिपाने की बातें उजागर हुईं। हालांकि, गिनी और अलग की गई नकदी को मंदिर से बैंक तक ले जाने के दौरान चोरी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आए 70 कथित मामलों की तुलना में SIT की विस्तृत जांच में यह संख्या 105 तक पहुंच गई है, जो जांच की गहराई को



दर्शाती है।

SIT ने चढ़ावे के तहत मिलने वाली कीमती वस्तुओं की भी अलग से विस्तृत जांच की। मंदिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड में दर्ज 803 कीमती वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया, और अधिकारियों के अनुसार उनका रिकॉर्ड से मिलान करने पर कोई भी अंतर नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, 86 ऐसी कीमती वस्तुओं की भी जांच की गई, जिनकी रसीद उपलब्ध नहीं थी, ताकि किसी भी अनियमितता का पता लगाया जा सके।

चांदी से जुड़े मामलों में करीब 944.411 किलोग्राम चांदी को भी प्रमाणित किया गया। जांच में 200 किलोग्राम चांदी की ईंटों और 38.288 किलोग्राम की एक अन्य खेप समेत कई चढ़ावों का रिकॉर्ड भी विस्तार से खंगाला गया।

मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने लगभग 79.85 लाख रुपये की नकदी बरामद होने की जानकारी दी है। SIT ने आरोपियों के बैंक खातों, जमा-निकासी, संपत्तियों, वाहनों, आभूषणों

और निर्माण कार्यों पर हुए खर्च की भी गहन पड़ताल की। जांच में यह भी देखने की कोशिश की गई कि उनकी संपत्ति और खर्च ज्ञात आय के स्रोतों से मेल खाते हैं या नहीं, ताकि किसी वित्तीय अनियमितता का पता चल सके। इस वित्तीय जांच के साथ-साथ फॉरेंसिक ऑडिट को भी चार्जशीट का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। जांच के दौरान SIT ने मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, CCTV ऑपरेटरों, चार्टर्ड अकाउंटेंट

और अन्य संबंधित लोगों समेत कुल 173 गवाहों के बयान दर्ज किए, जो जांच की व्यापकता और गंभीरता को दर्शाता है।

चार्जशीट में आठ आरोपियों: अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नु, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, रामाशंकर मिश्रा और करुणेश पांडेय के खिलाफ जांच के निष्कर्ष विस्तार से रखे गए हैं। इन आरोपियों को 26 जून को गिरफ्तार किया गया था और 90 दिन की कानूनी अवधि पूरी होने से पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई। अब इस मामले में अदालत चार्जशीट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी, जो इस मामले के निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

बैंककर्मियों को आरोपी ना बनाने पर सवाल

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की चार्जशीट में बैंककर्मियों को आरोपी नहीं बनाए जाने पर कई सवाल उठे हैं। प्रारंभिक SIT जांच में चढ़ावे की गिनती और बैंक तक रकम पहुंचाने की जिम्मेदारी में लगे बैंक अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख किया गया था। जांच में यह भी पता चला था कि बैंक अधिकारियों को गणना कर्मियों के साथ रोटेशन पर तैनात किया जाना था और उन्हें निर्धारित वर्दी उपलब्ध करानी होती थी, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बावजूद, अंतिम चार्जशीट में बैंककर्मियों को आरोपी नहीं बल्कि गवाह के रूप में शामिल किया गया है।

मुख्य सवाल यही है कि जब जांच में बैंकिंग व्यवस्था और उससे जुड़े कर्मचारियों की भूमिका पर संदेह था, तो उनकी आपराधिक जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई। हालांकि, प्रशासनिक लापरवाही और आपराधिक संलिप्तता अलग-अलग बातें हैं, और आरोपी बनाने के लिए जांच एजेंसी को पर्याप्त कानूनी साक्ष्य चाहिए। चार्जशीट में चोरी की 105 घटनाओं की CCTV फुटेज की जांच और 173 लोगों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन बैंककर्मियों के खिलाफ अभियोजन योग्य साक्ष्य न मिलने के कारण उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया।

करीब 10 साल बाद बाराबंकी की झीलों में लौटे सारस



करीब एक दशक बाद बाराबंकी की झीलों में सारस ने फिर घोंसले बनाकर प्रजनन शुरू किया है। मंजीठा के पास कमरावां गांव की झील में कई जगह सारस के घोंसले मिले हैं, जबकि रसौली की झील में इनका नियमित बसेरा दर्ज किया गया है। वन विभाग के अनुसार वर्ष 2024 की ग्रीष्मकालीन गणना में जिले में 257 सारस मिले थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 380 हो गई है। सारस की वापसी को जिले में वेटलैंड संरक्षण के प्रयासों का अहम संकेत माना जा रहा है। वन विभाग ने करीब 401 वेटलैंड चिह्नित किए हैं, जिनमें 12 बड़े वेटलैंड को प्रमुखता से संरक्षित और मॉनिटर किया जा रहा है। कमरावां में घोंसले और प्रजनन की गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि इन जलक्षेत्रों में पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण विकसित हुआ है। सारस की सुरक्षा के लिए हर रेंज में विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है और विभाग अब अन्य वेटलैंड को भी पक्षियों के सुरक्षित आश्रयस्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी में है।

सख्त हुआ ड्राइविंग टेस्ट, 70 फीसदी घटे आवेदन लाइसेंस की प्रक्रिया आसान होना अलग बात है, लेकिन बिना पर्याप्त जांच के सड़क पर उतरने वाले चालक पूरे यातायात तंत्र के लिए जोखिम बन सकते हैं

बाराबंकी में ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था सख्त होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन करीब 70 फीसदी घट गए हैं। पहले एआरटीओ कार्यालय में रोजाना 70 से 80 लर्निंग और स्थायी लाइसेंस के आवेदन आते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर 20 से 25 रह गई है। साथ ही टेस्ट देने वाले आवेदकों में आधे से अधिक पहली कोशिश में फेल हो रहे हैं। करीब छह महीने पहले टेस्टिंग की जिम्मेदारी निजी फर्म को दिए जाने के बाद अब आवेदकों को निर्धारित मानकों वाले ट्रैक पर वाहन चलाकर अपनी दक्षता साबित करनी पड़ रही है।

इस गिरावट को केवल आवेदकों की परेशानी के तौर पर देखना भी पूरी तस्वीर नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस महज एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि यह प्रमाणित करने की व्यवस्था है कि व्यक्ति सड़क पर वाहन चलाने की न्यूनतम क्षमता रखता है। केंद्र के परिवहन पोर्टल के मुताबिक स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदक को सक्षम प्राधिकारी के सामने अपनी ड्राइविंग क्षमता और निर्धारित कार्यों को पूरा करने की योग्यता साबित करनी होती है। ऐसे में ढीली या औपचारिक टेस्टिंग से लाइसेंस की संख्या तो बढ़ सकती है, लेकिन सड़क सुरक्षा के उद्देश्य कमजोर पड़ सकते हैं।

समस्या का दूसरा पहलू यह है कि सख्त व्यवस्था तभी असरदार होगी, जब उसके साथ पर्याप्त और सुलभ

प्रशिक्षण भी उपलब्ध हो। बाराबंकी में आवेदकों का कहना है कि पहली बार टेस्ट में असफल होने के बाद निजी फर्म की ओर से करीब छह हजार रुपये की ट्रेनिंग फीस बताई जा रही है, हालांकि एआरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है। यानी चुनौती सिर्फ टेस्ट पास करने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें सामान्य आवेदक को उचित लागत पर प्रशिक्षण, दोबारा परीक्षा और स्पष्ट जानकारी मिल सके।

यह बहस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क पर बिना वैध लाइसेंस या पर्याप्त प्रशिक्षण के वाहन चलाने की समस्या पहले से मौजूद है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की Road Accidents in India 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में लर्नर लाइसेंस वाले और बिना वैध लाइसेंस वाले चालकों से जुड़े हादसे कुल सड़क हादसों के 10.3 फीसदी थे। मंत्रालय ने बिना प्रशिक्षित और अयोग्य चालकों को गंभीर यातायात जोखिम बताते हुए बेहतर प्रशिक्षण, कौशल-विकास और मूल्यांकन की जरूरत रेखांकित की है।

इसलिए असली सवाल यह नहीं कि लाइसेंस कितनी आसानी से बनता है, बल्कि यह है कि सिस्टम से निकलने वाला चालक वास्तव में सड़क पर सुरक्षित ढंग से वाहन चलाने के लिए कितना तैयार है।

UPPSC परीक्षा पर सवाल: 80 फीसदी प्रश्न दोहराने का आरोप

असिस्टेंट प्रोफेसर गणित की परीक्षा में पुराने पेपर से सवाल दोहराने का अभ्यर्थियों का दावा, निष्पक्षता और परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की 18 सितंबर 2026 को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर (गणित) मुख्य परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि प्रश्नपत्र के 20 में 16 सवाल पुराने लेक्चरर भर्ती परीक्षा के प्रश्नों से हूबहू दोहराए गए, जबकि एक अन्य सवाल में मामूली बदलाव था और केवल तीन सवाल नए थे। अभ्यर्थियों के मुताबिक संबंधित पुरानी परीक्षा 19 सितंबर 2021 को आयोजित हुई थी। उनका कहना है कि अलग पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में इतने बड़े स्तर पर प्रश्न दोहराए जाने से परीक्षा की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है।

अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले लेक्चरर भर्ती परीक्षा दी थी, उन्हें पुराने प्रश्नों से पहले से परिचित होने का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। उनका तर्क है कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लेक्चरर और सरकारी डिग्री कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर अलग पद हैं, इसलिए दोनों परीक्षाओं के उद्देश्य और मूल्यांकन की प्रक्रिया भी अलग होनी चाहिए। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी दावा किया कि प्रश्नपत्र में दो सवाल निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर थे। इसी आधार पर उन्होंने प्रश्नपत्र की स्वतंत्र जांच, दोनों पेपरों की प्रश्न-दर-प्रश्न तुलना और जरूरत पड़ने पर परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग की है।

हालांकि अभी इन आरोपों को आयोग की ओर से स्थापित तथ्य के तौर पर

स्वीकार नहीं किया गया है। UPPSC के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने कहा कि आयोग को इस संबंध में जानकारी नहीं है और यदि अभ्यर्थी औपचारिक आपत्ति दाखिल करते हैं, तो मामला परीक्षा समिति के सामने रखा जाएगा। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर असिस्टेंट प्रोफेसर, सरकारी डिग्री कॉलेज परीक्षा-2025 के गणित पेपर को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया और उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच संभव है। ऐसे में आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों और प्रश्नपत्र की तुलना की आधिकारिक जांच में क्या सामने आता है।

अभ्यर्थियों के लिए मामला सिर्फ कुछ सवाल दोहराए जाने का नहीं है, बल्कि भर्ती परीक्षाओं में भरोसे और समान अवसर का भी है। सरकारी नौकरी की सीमित सीटों के लिए बड़ी संख्या में युवा वर्षों तक तैयारी करते हैं और एक परीक्षा में प्रश्नपत्र की गुणवत्ता या प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल सीधे उनके भविष्य से जुड़ जाते हैं।

इसलिए इस मामले में पारदर्शिता महत्वपूर्ण होगी की कौन से प्रश्न दोहराए गए, वे निर्धारित पाठ्यक्रम में थे या नहीं, प्रश्नपत्र तैयार करने और मॉडरेशन की प्रक्रिया कैसे हुई और क्या किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ मिला। इन सवालों के तथ्यात्मक जवाब ही विवाद को स्पष्ट कर सकते हैं।

₹25 हजार की सैलरी में 2026 में अकेले रहना कितना मुश्किल?

किराया, खाना, सफर, EMI और OTT के बाद युवा के हाथ में कितनी बचत? दिल्ली-मुंबई से लेकर लखनऊ और कानपुर तक बदलती है जिंदगी की कीमत

नई दिल्ली।

नौकरी लगने के बाद पहली बार घर से दूर शहर में रहने का सपना आज के युवा के लिए जितना आकर्षक है, उसका गणित उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। महीने की ₹25,000 सैलरी सुनने में शुरुआत के लिए ठीक लग सकती है, लेकिन 2026 में शहर की जिंदगी का हिसाब लगाएं तो सवाल खड़ा होता है। क्या इस रकम में एक युवा किराया, खाना, आने-जाने का खर्च, मोबाइल-इंटरनेट, मनोरंजन, EMI और थोड़ी-बहुत बचत के साथ वास्तव में स्वतंत्र जीवन जी सकता है?

इसका जवाब शहर के हिसाब से बदल जाता है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अकेले 1BHK लेकर रहना ₹25 हजार की आय में मुश्किल हो जाता है। वहीं लखनऊ और खासकर कानपुर जैसे शहरों में PG, साझा फ्लैट और नियंत्रित खर्च के साथ यह रकम गुजारा करने की गुंजाइश देती है। शहर और जीवनशैली के हिसाब से वास्तविक खर्च काफी बदल सकता है, लेकिन आवास आम तौर पर सबसे बड़ा खर्च बना हुआ है।

पहली तनखाह का सबसे बड़ा हिस्सा किराए में

₹25,000 की सैलरी में सबसे पहले किराए का सवाल आता है। दिल्ली में इलाके के अनुसार PG की कीमत करीब ₹7,000 से शुरू होकर काफी ऊपर जा सकती है। 1BHK का किराया बजट इलाकों में भी ₹10,000-15,000 या उससे अधिक हो सकता है। ऐसे में अकेले फ्लैट लेने के बाद खाने और बाकी जरूरी खर्चों के लिए बहुत कम रकम बचती है। बेंगलुरु में भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है। साझा फ्लैट, PG या co-living युवा कर्मचारियों के लिए अधिक व्यावहारिक विकल्प बनते हैं। ऑफिस के पास रहने का मतलब ज्यादा किराया और दूर रहने का मतलब ज्यादा सफर का खर्च और समय। युवा को अक्सर इन दोनों में संतुलन बनाना पड़ता है। मुंबई में गणित और कठिन हो जाता है। यहां ₹25 हजार की आय में अकेले रहने के बजाय PG या साझा कमरा लेना लगभग जरूरी विकल्प बन सकता है। किराए को कम करने के लिए शहर से दूर जाना पड़े तो सफर का खर्च और समय बढ़ जाता है।

दिल्ली: मेट्रो बचाती है, किराया बजट बिगाड़ता है

दिल्ली में ₹25 हजार की सैलरी पर सबसे व्यावहारिक विकल्प PG या साझा कमरा है। मेट्रो की वजह से दूर रहकर भी रोजाना का सफर संभाला जा सकता है, लेकिन घर और दफ्तर के बीच की दूरी बढ़ने पर समय की कीमत भी चुकानी पड़ती है।

अगर ₹8,000-10,000 किराए में चले गए, तो करीब ₹15-17 हजार में पूरे महीने का बाकी जीवन चलाना होगा। खाना, मोबाइल, यात्रा, कपड़े, दवाइयां और अचानक आने वाले खर्च इसी रकम से निकलेंगे। ऐसी स्थिति में अकेले 1BHK की बजाय रूममेट के साथ रहना आर्थिक मजबूरी से ज्यादा बजट की रणनीति बन जाता है।

बेंगलुरु: नौकरी के साथ किराए की चुनौती

बेंगलुरु में युवा प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा सवाल ऑफिस के आसपास रहने का है। IT कॉरिडोर और लोकप्रिय इलाकों में किराया तेजी से बढ़ सकता है। ₹25 हजार की सैलरी में अकेले फ्लैट लेने के बाद खाने, परिवहन और बाकी खर्चों के लिए बहुत कम रकम बचेगी। इसलिए PG, co-living या साझा फ्लैट ज्यादा व्यावहारिक विकल्प बनते हैं। यहां एक और खर्च तेजी

मुंबई में किराया बचाने और समय बचाने के बीच समझौता करना पड़ सकता है। घर सस्ता चाहिए तो ऑफिस से दूरी बढ़ सकती है और दूरी बढ़ने पर रोजाना का सफर महंगा और थकाऊ हो सकता है।

लखनऊ: ₹25 हजार में गुंजाइश, लेकिन आराम सीमित

लखनऊ में तस्वीर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की तुलना में कुछ बेहतर है। शहर के बाहरी इलाकों में अपेक्षाकृत कम किराए पर रहने की व्यवस्था मिल सकती है। साझा फ्लैट या PG चुनने पर युवा अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचा सकता है। लेकिन यहां भी ₹25 हजार की सैलरी का मतलब यह नहीं कि हर महीने आराम से बचत हो जाएगी। बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, कैब, मनोरंजन और EMI जुड़ते ही बजट तेजी से बिगड़ सकता है। जरूरत और lifestyle के बीच सीमा तय

निर्भर करती है। बाइक की EMI, फोन की EMI, बाहर खाना और ऑनलाइन खरीदारी जैसे खर्च जुड़ते ही बचत का गणित यहां भी बिगड़ सकता है।

EMI: छोटी रकम, बड़ा असर

आज के युवा के बजट में किराए के बाद EMI दूसरा ऐसा खर्च है जिसे नजरअंदाज करना आसान है। मान लीजिए फोन की EMI ₹2,000 है। ₹25 हजार की सैलरी में यह रकम मामूली नहीं है। यह महीने के कुल वेतन का 8 प्रतिशत है। अगर बाइक की EMI ₹3,000 और फोन की EMI ₹2,000 है, तो केवल इन दो चीजों में ₹5,000 चले गए। यानी वेतन का पांचवां हिस्सा सिर्फ EMI में। इसके बाद किराया, खाना और सफर जोड़ते ही बचत के लिए जगह बहुत कम रह जाती है।

सवाल सिर्फ महीने के आखिरी दिन तक पहुंचने का नहीं

₹25 हजार की सैलरी में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि महीना निकल जाएगा या नहीं। असली सवाल है कि महीने के अंत में कितना बचेगा। अगर अचानक ₹5,000 का मेडिकल खर्च आ जाए, बाइक खराब हो जाए या घर जाने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ जाएं तो क्या बजट संभल पाएगा? यही वजह है कि कम सैलरी में आपातकालीन बचत बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। शुरुआत में हर महीने बड़ी रकम बचाना संभव न हो, फिर भी छोटी नियमित बचत युवा को अगले अप्रत्याशित खर्च के सामने कर्ज लेने से बचा सकती है।

तो क्या ₹25 हजार में युवा स्वतंत्र रह सकता है?

रह सकता है, लेकिन स्वतंत्रता की परिभाषा बदलनी होगी। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में अकेले 1BHK,



से बजट बिगाड़ सकता है: कैब और बाइक से रोजाना आना-जाना। किराया कम करने के लिए दूर रहना और फिर रोजाना महंगा सफर करना कई बार कुल खर्च को कम करने के बजाय बढ़ा देता है।

मुंबई: ₹25 हजार में 'स्वतंत्र जिंदगी' का सबसे कठिन गणित

मुंबई में ₹25 हजार की सैलरी और अकेले रहने का सपना सबसे कठिन समीकरणों में से एक है। शहर में किराया आम तौर पर आय का बड़ा हिस्सा खा सकता है। ऐसे में युवा को PG, साझा कमरा या शहर के अपेक्षाकृत दूर इलाकों का विकल्प चुनना पड़ सकता है।

करना यहां भी जरूरी है।

कानपुर: ₹25 हजार में थोड़ी ज्यादा गुंजाइश

कानपुर में ₹25 हजार की आय का गणित महानगरों की तुलना में कुछ आसान हो सकता है। किराया अपेक्षाकृत कम होने के कारण युवा की आय का छोटा हिस्सा आवास पर खर्च हो सकता है। अगर रहने के लिए सही इलाका चुना जाए और रोजाना के सफर का खर्च नियंत्रित रखा जाए तो भोजन और दूसरी जरूरतों के बाद कुछ रकम बचाने की गुंजाइश बन सकती है।

लेकिन यह तस्वीर भी जीवनशैली पर

OTT, फूड डिलीवरी और 'छोटे खर्चों' का बड़ा बिल

युवा की जिंदगी में हर खर्च किराया या EMI जैसा बड़ा नहीं होता। ₹149 का OTT, ₹299 का म्यूजिक या ऐप सब्सक्रिप्शन, सप्ताह में दो बार ₹300-400 का ऑनलाइन खाना और महीने में कुछ शॉपिंग। हर खर्च अलग-अलग छोटा दिखता है। लेकिन महीने के अंत में यही छोटे भुगतान ₹2,000-4,000 तक पहुंच सकते हैं। ₹25 हजार की सैलरी में ₹3,000 का ऐसा खर्च 12 प्रतिशत आय के बराबर है। यही वह अंतर है जहां 'गुजारा हो रहा है' और 'स्वतंत्र जीवन जी रहा हूँ' के बीच की रेखा दिखाई देती है।

रोजाना कैब, बाहर खाना, EMI और नियमित मनोरंजन के साथ ₹25 हजार की सैलरी का बजट टिकना मुश्किल है। वहीं लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में साझा आवास, घर के खाने और नियंत्रित यात्रा के साथ यह संभव हो सकता है।

असल सवाल केवल यह नहीं है कि ₹25 हजार में महीना निकल जाएगा या नहीं। सवाल यह है कि महीना निकालने के बाद कितना बचेगा, अचानक आए ₹5,000 के खर्च का क्या होगा और नौकरी छूटने पर कितने दिन बिना किसी मदद के गुजारा हो सकेगा।